भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1346
जिसका उत्तर दिनांक मंगलवार, 17 दिसम्बर, 2013 को दिया जाना है

विनिर्माण क्षेत्र का प्रौद्योगिकीय उन्नयन

1346. श्री हुसैन दलवई:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एक अग्रणी विनिर्माता बनने के लिए देश के विनिर्माण क्षेत्र का विकास और प्रौद्योगिकीय उन्नयन किए जाने की जरूरत है;
(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और
(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री
(श्री प्रफुल पटेल)

(क): जी, हां।

(ख): भारत पारम्परिक रूप से प्रौद्योगिकी का आयात करता रहा है क्योंकि देश उत्पाद अभिकल्प और विनिर्माण में वैश्विक स्तर की प्रतिस्पर्धात्मकता में पीछे है। विश्वस्तरीय प्रतिस्पर्धात्मकता प्राप्त करने के लिए प्रौद्योगिकीय विकास तथा उत्पाद उन्नयन महत्वपूर्ण हैं। उच्च स्तर की प्रौद्योगिकियों की अनुपलब्धता भारतीय विनिर्माण क्षेत्र के विकास की राह में बाधा रही है।

(ग): उपयुक्त नीति समर्थन के साथ घरेलू मूल्य संवर्धन और भारतीय विनिर्माणकारी वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए विनिर्माण में प्रौद्योगिकीय पहुंच के विचार से सरकार ने राष्ट्रीय विनिर्माण नीति पेश की है। प्रौद्योगिकी अधिग्रहण और विकास के लिए वित्तीय और संस्थागत तंत्र जैसे उपायों को विनिर्माण नीति में वर्णित किया गया है। यह नीति स्थानीय मूल्य संवर्धन पर जोर डालते हुए विनिर्माण उद्योग और प्रौद्योगिकीय प्रतिस्पर्धात्मकता के विकास को सुदृढ़ करने हेतु सरकारी अधिप्राप्ति के लिए एक नीति के साधन के रूप में प्रयोग में लाने की व्यवस्था करती है। प्रौद्योगिकी और विनिर्माण में प्रौद्योगिकीय पहुंच की सहायता के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना में एक विनिर्माण योजना तैयार की गई है। सरकार ने प्रौद्योगिकी के आयात की स्वतंत्रता और 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देते हुए प्रौद्योगिकीय परिष्करण को प्रोत्साहन प्रदान किया है।

*****